वर्ष-14 - अंक 94
पृष्ट-04 मूल्य : 01 रुपया

सीतापुर
सोमवार ,13 जुलाई 2026

RNI.No. UHIN/2012/43078

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

swatantraprabhat.com

epaper.swatantraprabhat.com

जो लिखेगा, वही टिकेगा

लखनऊ से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून गाज़ियाबाद , दिल्ली ,पंजाब , हरियाणा ,चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में विदाई एवं सम्मान समारोह संपन्न 3

मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान, असम राइफल्स हमले के बाद सर्च ऑपरेशन तेज 4

स्वर्णिम लक्ष्यों के साथ 2047 तक कृषि महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश 02

राम मंदिर के VIP पास पर बवाल; जानें कौन करता है जारी, कैसे बनते हैं और क्यों उठ रहे सवाल

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद खूब बवाल मचा. स्ट्रक्ष की जांच के बाद 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया. राम मंदिर ट्रस्ट में प्रबंधन की भूमिका निभा रहे पदाधिकारियों की भूमिका पर कई सवाल उठे. इसके अलावा रामलला के दर्शन के लिए वीआईपी पास जारी करने की प्रक्रिया में भी गड़बड़ियों का भी मामला सामना आया. आरोप यह भी लगे कि वीआईपी पास जारी कर रामलला के दर्शन के लिए भक्तों से वसूली की जा रही है. राम मंदिर में VIP पास एक विशेष प्रवेश व्यवस्था है. इसके जरिए कुछ लोगों को सामान्य कतार से अलग या प्राथमिकता के साथ दर्शन की सुविधा दी जाती है. यह पास आमतौर पर वरिष्ठ नागरिकों, सरकारी अधिकारियों, और मंदिर के विशेष अतिथियों के लिए होते हैं. इसे सुगम दर्शन पास भी कहा जाता है.

अब तक रामलला के दर्शन के लिए कौन करता था वीआईपी पास जारी?

अब तक ट्रस्ट के महासचिव ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की आईडी के जरिए वीआईपी दर्शन पास किए जाते हैं. यानी पास जारी करने का अधिकार उन्हीं के पास था. आसान भाषा में समझे तो अगर ट्रस्ट के सदस्य VIP दर्शन पास सीधे अपने डिजिटल अकाउंट या सिफारिशी पत्र से किसी व्यक्ति के नाम जारी करते हैं. फिर पास काउंटर पर बैठे लोग इस डिजिटल सिस्टम के जरिए आए ऑनलाइन अनुरोध या उनकी मुहर लगे कागजों का सत्यापन (वेरिफिकेशन) कर पास जारी करते थे.

ट्रस्ट ने वीआईपी पास जारी करने की व्यवस्था में क्या-क्या बदलाव किए?

चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को वीआईपी दर्शन पास जारी कराने का अधिकार प्राप्त था. हालांकि अब यह जिम्मेदारी ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास को सौंप दी गई है. चंपत राय, अनिल मिश्रा की पास जारी करने की डिजिटल आईडी सस्पेंड पदाधिकारियों की डिजिटल आईडी का दुरुपयोग कर अंधाधुंध पास जारी करने का मामला सामने आया था ट्रस्ट के अधिकृत पदाधिकारी के अलावा और कौन जारी कर सकता है वीआईपी पास? राम मंदिर में वीआईपी पास निशुल्क बनता है. इसके लिए पैसे लेने की कोई व्यवस्था है. हालांकि, एसआईटी की जांच में इसमें भी गड़बड़ियां सामने आई है. वीआईपी पास केवल अधिकृत व्यक्तियों की सिफारिश और पहले से तय प्रक्रिया के तहत ही जारी किए जाते हैं. ट्रस्ट के अधिकृत पदाधिकारी के आलावा इस पास को अयोध्या के डीएम, एसएसपी, डीआईजी भी वीआईपी पास जारी कर सकते हैं. इन चारों अधिकारियों को प्रशासन की तरफ से 200-200 पास जारी करने की सुविधा मिली हुई है. वहीं ट्रस्ट की तरफ से पास जारी करने की कोई निर्धारित सीमा नहीं है. लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बयानों के मुताबिक यहां से रोजाना 100 से लेकर 200 पास जारी किए जाते हैं. लेकिन एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया है कि ट्रस्टियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की डिजिटल आईडी का दुरुपयोग कर अंधाधुंध वीआईपी पास जारी किए गए. यही वजह है कि अब चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के क्रेडेंशियल को डिएक्टिवेट कर, सिर्फ दिनेंद्र दास की आईडी पर पास जारी किए जाएंगे.

ऑनलाइन वीआईपी पास के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है?

पास बनवाने के लिए सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट online.srjbtkshetra.org पर जाएं. इसके बाद आपको होमपेज पर नीचे पास बनवाने से जुड़ा लिंक मिलेगा, जहां क्लिक करें. इसके बाद अलग-अलग आरती और दर्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जिस ऑप्शन के लिए पास बनवाना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें. आपके सामने फोन नंबर का ऑप्शन आएगा. आप फोन नंबर एंटर करें और ओटीपी के जरिए लॉगिन कर लें. आप ईमेल आईडी के जरिए भी लॉगिन कर सकते हैं. इसके बाद आपके सामने ऊपर दी गई स्क्रीन आएगी. जहां आपको डिटेल भरनी है. इसमें आपको कितने लोगों के पास चाहिए, उसकी डिटेल भरनी होगी. आप एक लॉगिन से सिर्फ 5 लोगों का ही पास बनवा सकते हैं. फिर आप तारीख आदि भरें. तारीख आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करनी होगी. इसमें जिस तारीख पर हरा बॉक्स होगा, उसका पास मिल जाएगा. इसमें अगले 15 दिनों की तारीख सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर लाल बॉक्स आ रहा है तो समझ जाइए कि उस तारीख की पास लिमिट खत्म हो चुकी है. अगर आपको किसी दिन का ग्रीन बॉक्स मिलता है यानी स्लॉट मिलता है तो आप सेलेक्ट कर अपना पास हासिल कर सकते हैं. अप्रूवल के बाद ऑनलाइन ही आप अपना पास डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे करते हैं वीआईपी पास के लिए अप्लाई? ऑफलाइन तरीके से वीआईपी पास या सुगम दर्शन पास के लिए पास काउंटर पर जाकर एक निर्धारित फॉर्म भरना होता है. इसमें श्रद्धालुओं का नाम, उम्र, जेंडर और पहचान पत्र की डिटेल देना होता है. ऑफलाइन में एक फॉर्म पर अधिकतम 8 लोगों को पास जारी किया जा सकता है. जिस पदाधिकारी और अधिकारी के नाम से श्रद्धालु को पास जारी होता है, उसका नाम भी उसमें दर्ज होता है.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में CBI जांच की मांग, कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा. सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वीएस मोहना की पीठ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी. कोर्ट वकील अजय कुमार राय, वकील दिनेश कुमार यादव और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. पिछली सुनवाई की अवकाशकालीन पीठ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सीबीआई की निगरानी में समिति गठित कर पूरे मामले की जांच की मांग की गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दान की राशि में कोई गबन, भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता हुआ है या नही. यह सुनवाई ऐसे समय में हो रही है जब उत्तर प्रदेश में कथित गबन की जांच जारी है. 7 जुलाई को, अयोध्या की एक अदालत ने मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों में से तीन अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को एक दिन की पुलिस कस्टडी दी थी. इससे पहले, 29 जून को, एक लोकल अदालत ने सभी आठ आरोपियों को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था.

चढ़ावा चोरी की SIT कर रही है जांच

दान में हेराफेरी के आरोप सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को तीन सदस्यों वाली एसआईटी बनाई थी. एसआईटी में लखनऊ डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत, पुलिस इंस्पेक्टर जनरल किरण एस और स्पेशल सेक्रेटरी (फाइनेंस) नील रतन शामिल हैं. एसआईटी की शुरुआती जांच में मंदिर के काउंटिंग रूम में गंभीर सुरक्षा चूक की ओर इशारा किया गया है और यह सुझाव दिया गया है कि कथित चोरी 'सिस्टेमैटिक' थी और अलग-अलग नहीं बल्कि बार-बार हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद 27 अप्रैल से 5 जून के बीच करीब 70 संदिग्ध घटनाएं हुई, जिनमें काउंटिंग स्टाफ कथित तौर पर अपने कपड़ों, जेबों, जूतों और दूसरे निजी सामान में कैश के बंडल छिपाते हुए देखे गए थे.

चढ़ावा चोरी पर गरमाई सियासत

शुरुआती जांच में सिक्योरिटी इंतजामों में कमियां भी सामने आई, जिसमें काउंटिंग हॉल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर स्टाफ की तलाशी न लेना और निजी सामान की ठीक से मॉनिटरिंग न होना शामिल है. मंदिर ट्रस्ट के सदस्य ने जांच का समर्थन किया. चल रहे विवाद के बीच, श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज ने जांच पर भरोसा जताया और उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों के VIP दर्शन पास आईडी ब्लॉक कर दिए गए थे. इस कथित गबन ने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें विपक्षी पार्टियां जवाबदेही की मांग कर रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के लिए आए दान का गलत इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है.

संक्षिप्त ख़बरें

नृपेंद्र मिश्र बोले- चढ़ावा चोरी 'कलंक', व्यवस्था में होगा सुधार

ब्यूरो प्रयागराज। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर में सामने आए चढ़ावा चोरी प्रकरण को 'कलंक' बताते हुए कहा कि लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। ऐसे में इस प्रकार की घटना हम सभी को छोटा महसूस कराती है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार किए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। शनिवार को अयोध्या में पत्रकारों से बातचीत के दौरान नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।समिति की संस्तुति के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अंतिम निर्णय करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शनिवार को होने वाली बैठक पूरी तरह निर्माण कार्यों पर केंद्रित है। इस बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारी शामिल नहीं होंगे। बैठक में केवल निर्माण कार्य से जुड़ी कार्यदायी संस्थाओं और कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ परियोजना की प्रगति और शेष कार्यों की समीक्षा की जाएगी। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि शुक्रवार को उन्होंने राम मंदिर परिसर का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की थी। उन्होंने विश्वास जताया कि मंदिर परिसर में चल रहे शेष निर्माण कार्य 20 जुलाई तक पूरे कर लिए जाएंगे। साथ ही कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

72 घंटे बाद भी जारी रेस्क्यू, मृतकों की संख्या बढ़कर आठ

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे जिले के मोशी स्थित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट में हुए भीषण हादसे के 72 घंटे बाद भी राहत एवं बचाव अभियान जारी है। शनिवार को अभियान के चौथे दिन मलबे से सात और शव बरामद किए गए, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। अब तक मलबे में फंसे 23 लोगों में से 14 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। यह हादसा बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे उस समय हुआ, जब पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम (पीसीएमसी) के वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट में कचरे का विशाल ढेर अचानक प्रशासनिक भवन पर गिर गया। भारी दबाव के कारण तीन मंजिला इमारत पलभर में ढह गई। घटना के समय भवन में 23 कर्मचारी मौजूद थे, जिनमें से पांच लोग स्वयं बाहर निकलने में सफल रहे।

उत्तराखंड में भारी बारिश का असर: 91 सड़कें बंद, 11 बांध-बैराज में जलस्तर खतरे के निशान के करीब

देहरादून(एजेंसी)। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। राज्यभर में एक राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) और दो राज्य राजमार्ग (स्टेट हाईवे) सहित कुल 91 सड़कें बंद हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) बंद मार्गों को जल्द से जल्द खोलने के लिए युद्धस्तर पर राहत एवं मरम्मत कार्य में जुटा है। सबसे अधिक प्रभावित पौड़ी गढ़वाल जिला है, जहां 21 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा चमोली में 19, टिहरी में 17, पिथौरागढ़ में 10, उत्तरकाशी में एक राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 8, हरिद्वार में 4, बागेश्वर में 4, अल्मोड़ा में 3, रुद्रप्रयाग में 3, देहरादून में 1 और चंपावत में 1 सड़क पर

यातायात बाधित है। इधर, लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के 11 बांध और बैराजों में जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। शुक्रवार सुबह उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के समीप पहुंच गया था और इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं कोटेश्वर और रुद्रप्रयाग क्षेत्र में भी नदी का जलस्तर खतरे के स्तर के करीब पहुंच गया। बदरीनाथ में अलकनंदा नदी का जलस्तर भी कुछ समय के लिए खतरे के निशान के करीब पहुंचा, हालांकि बाद में इसमें कमी दर्ज की गई। दूसरी ओर ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर धीरे-धीरे घटने लगा है, जिससे प्रशासन को कुछ राहत मिली है। राज्य प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा मौसम विभाग द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की है।

छाती में धंसा चाकू निकालकर युवक की बचाई जान

लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सकों ने एक बेहद जटिल सर्जरी कर छाती में धंसे चाकू के साथ पहुंचे युवक की जान बचाने में सफलता हासिल की है। ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर केजीएमयू के कुलपति ने ऑपरेशन करने वाली पूरी मेडिकल टीम को बधाई दी है। जानकारी के अनुसार, लखीमपुर खीरी निवासी सर्वेश पर 4 जुलाई की रात करीब नौ बजे चाकू से हमला किया गया था। हमले में चाकू उनकी दाहिनी छाती में गहरे तक धंस गया और फेफड़े के अत्यंत संवेदनशील हिस्से तक पहुंचकर प्रमुख रक्त वाहिकाओं को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।

पार्टी जो कहेगी वही करूंगा, किसी से कोई नाराजगी नहीं : टिकट विवाद के बीच बोले नरोत्तम मिश्रा

भोपाल/दतिया(एजेंसी)। दतिया विधानसभा उपचुनाव 2026 में टिकट को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को भोपाल पहुंचकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पार्टी के निर्णय का सम्मान करते हैं और संगठन जो जिम्मेदारी देगा, उसका पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। डॉ. मिश्रा ने अपने समर्थकों से धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता उनकी ताकत हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई बात रखनी है तो वह पार्टी के निर्धारित मंच और प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखें। उन्हें विश्वास है कि कार्यकर्ता अनुशासन का परिचय देंगे और पार्टी की मर्यादा बनाए रखेंगे। भाजपा नेतृत्व से बातचीत के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी आवश्यक होगा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जाएगी। वहीं, दतिया से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के चुनाव प्रचार और नामांकन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें दतिया जाना चाहिए और वह स्वयं भी नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। टिकट नहीं मिलने के बावजूद किसी तरह की नाराजगी से इनकार करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा, 'पार्टी जो कहेगी, वही करूंगा। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है।' जब उनसे पूछा गया कि टिकट कटने की जानकारी उन्हें कब मिली, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'जब आपको पता चला, तब मुझे भी पता चला।

13 जुलाई को लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे राजनाथ सिंह

लखनऊ(एजेंसी)। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार, 13 जुलाई को एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। अपने दौरे के दौरान वह लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा वह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के 22वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे तथा सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के अनुसार, रक्षा मंत्री सोमवार सुबह 10:35 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। यहां से वह सीधे केजीएमयू जाएंगे, जहां सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित 22वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे और उपाधियां प्रदान करेंगे। दीक्षांत समारोह के बाद रक्षा मंत्री अपने सरकारी आवास जाएंगे। इसके पश्चात दोपहर 3 बजे वह ला मार्टिनियर कॉलेज हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्नाव के लिए

आरोपी हिजबुल कमांडर पर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी

श्रीनगर(एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) को वर्ष 2013 के आतंकी हमले की जांच में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। एजेंसी ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के नामित आतंकी इम्तियाज अहमद कंडू उर्फ फैयाज उर्फ सज्जाद के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी कराया है। इससे आरोपी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तलाश और भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। एसआईए के अधिकारियों के अनुसार यह मामला वर्ष 2013 में उत्तर

कश्मीर के बारामुला जिले के तरजू क्षेत्र में हुए आतंकी हमले से जुड़ा है। इस हमले में जम्मू-कश्मीर पुलिस के चार जवान शहीद हो गए थे। एजेंसी का कहना है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां आरोपी का पता लगाने, उसे हिरासत में लेने और कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत भेजने में सहयोग कर सकेंगी। जांच में सामने आया है कि सोपोर के क्रालटंग निवासी इम्तियाज कंडू वर्ष 2010 से प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य और कमांडर रहा है। भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में उसे नामित व्यक्तिगत आतंकी घोषित किया था। यह मामला पहले तरजू थाने में दर्ज किया गया था, जिसे वर्ष 2024 में आगे की जांच के लिए एसआईए को सौंप दिया गया। विस्तृत जांच, साक्ष्यों के संग्रह और गवाहों से पूछताछ के बाद एजेंसी ने जुलाई 2024 में छह आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। जांच के दौरान नामजद छह आरोपियों में से तारीक अहमद मीर और कयूम नजर सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। वहीं जाविद अहमद मट्टू, रऊफ नजर और अहमदुल्ला मल्ला गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। मुख्य आरोपी इम्तियाज कंडू अब भी फरार है और उसके पाकिस्तान में छिपे होने की आशंका जताई गई है।

रविवार को यूपी में 35 करोड़ पौधों का महाअभियान, गोरखपुर से सीएम योगी करेंगे शुभारंभ

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेशभर में होगा वृक्षारोपण, ऑनलाइन होगी पल-पल की मॉनिटरिंग

लखनऊ(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार, 12 जुलाई को 'पौधरोपण महायज्ञ-2026 : एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पौधरोपण कर इस राज्यव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। वन विभाग के अनुसार, अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में किए जाने वाले पौधरोपण की प्रगति को वृक्षारोपण

मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। वन विभाग के अनुसार, अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में किए जाने वाले पौधरोपण की प्रगति को वृक्षारोपण सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। पौधरोपण की क्षण-प्रतिक्षण निगरानी की जाएगी, जिससे अभियान की पारदर्शिता और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और आम नागरिकों से इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जन-जागरूकता को भी बढ़ावा देना है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी में तथा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमों में शामिल होकर पौधे लगाएंगे। प्रदेश सरकार का लक्ष्य इस महाअभियान के माध्यम से हरित क्षेत्र का विस्तार करना, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करना तथा जनसहभागिता के जरिए पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देना है।

बदरीनाथ चढ़ावा हेराफेरी: निलंबित कर्मचारी पहुंचा हाईकोर्ट

याचिका पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 16 जुलाई को सुनवाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की 'थाली भेंट' की गिनती के दौरान कथित वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित पक्षों से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के समक्ष हुई। याचिका के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को बदरीनाथ मंदिर समिति को सूचना मिली थी कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई 'थाली भेंट' की नकद राशि की गिनती के दौरान कथित अनियमितता हुई है। इसके बाद समिति अध्यक्ष के निर्देश पर एक विभागीय जांच समिति गठित की गई। प्रारंभिक जांच में समिति ने पाया कि मंदिर समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने कथित तौर पर सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे के बीच थाली भेंट की गिनती स्थल से नियमों का उल्लंघन करते हुए नकदी उठाई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मंदिर समिति ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके बाद श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान ने कोतवाली श्री बदरीनाथ में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

संपादकीय

यूपी की जिला पंचायतों में नया प्रयोग

उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। राज्य सरकार ने सभी 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें ही प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब तक कार्यकाल समाप्त होने पर आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासक बनाया जाता था, लेकिन पहली बार निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों को ही सीमित अधिकारों के साथ प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का कहना है कि इससे विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और पंचायत चुनावों में देरी से जोड़कर सवाल उठा रहा है। क्या है सरकार का फैसला ?- उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने सभी मौजूदा अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। हालांकि, उन्हें केवल नियमित प्रशासनिक और आवश्यक कार्यों तक ही सीमित रखा गया है। वे कोई नई योजना, बड़े वित्तीय निर्णय या नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। उनका मुख्य दायित्व पंचायत प्रशासन को सुचारु रूप से चलाना होगा, जब तक कि नए चुनाव संपन्न नहीं हो जाते। पहले क्या व्यवस्था थी ?- अब तक यदि किसी पंचायत निकाय का कार्यकाल समाप्त हो जाता था और समय पर चुनाव नहीं हो पाते थे, तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासक बनाया जाता था। जिला पंचायतों में यह जिम्मेदारी प्रायः वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाती थी। इस बार सरकार ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही यह जिम्मेदारी देकर एक अलग व्यवस्था लागू की है। सरकार का तर्क है कि चुने हुए प्रतिनिधि स्थानीय आवश्यकताओं और विकास कार्यों को बेहतर ढंग से समझते हैं। सरकार की दलील- सरकार का कहना है कि पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने तक विकास कार्य पूरी तरह रुकने नहीं चाहिए। यदि पूरी व्यवस्था अधिकारियों के भरोसे छोड़ दी जाए तो स्थानीय स्तर पर कई कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए निर्वाचित अध्यक्षों को सीमित अधिकारों के साथ प्रशासक बनाना प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने का बेहतर तरीका है। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रशासक के रूप में वे केवल नियमित कार्य करेंगे और कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे। विपक्ष के आरोप- विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार पंचायत चुनाव समय पर कराने में असफल रही है और प्रशासक नियुक्त कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लंबा खींच रही है। उनका कहना है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द नए चुनाव कराए जाने चाहिए। विपक्ष इसे पंचायत चुनावों में देरी का परिणाम बता रहा है। कानूनी और संवैधानिक पहलू,- इस तरह ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सरकार से संवैधानिक आधार पर सवाल पूछे हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि कहीं यह व्यवस्था निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने जैसी तो नहीं है। अदालत ने सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्षों के मामले पर भी कानूनी और संवैधानिक बहस तेज हो सकती है। क्या होंगे प्रशासकों के अधिकार ?- प्रशासक के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष—0नियमित प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे। आवश्यक भुगतान और दैनिक कार्यों की निगरानी करेंगे। नई योजनाओं की शुरुआत नहीं करेंगे। बड़े वित्तीय या नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। चुनाव होने तक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करेंगे। पंचायत चुनावों पर नजर- अब सबसे बड़ा सवाल पंचायत चुनावों की समयसीमा को लेकर है। यदि चुनाव शीघ्र कराए जाते हैं तो यह व्यवस्था केवल अस्थायी साबित होगी। लेकिन यदि चुनाव में अधिक विलंब होता है तो सरकार को राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग भविष्य में चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने का निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से नया प्रयोग माना जा सकता है। सरकार इसे विकास कार्यों की निरंतरता का माध्यम बता रही है, जबकि विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया और समय पर चुनाव कराने की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। आने वाले दिनों में न्यायालय की टिप्पणियां, राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां और पंचायत चुनावों की घोषणा इस पूरे मुद्दे की दिशा तय करेंगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि प्रशासकों को सीमित अधिकार दिए गए हैं और उनका कार्य पंचायत प्रशासन को सुचारु बनाए रखना है, न कि बड़े नीतिगत फैसले लेना।

राजीव शुक्ला -(संपादक)

मेष -मेष राशि के जातकों को आज अपने अधूरे कार्यों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। दूसरों की समस्याओं में अधिक समय लगाने से पहले अपने दायित्व पूरे करना बेहतर रहेगा। प्रतिस्पर्धी माहौल में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है।

वृषभ -वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सूझबूझ और बेहतर प्रबंधन का रहेगा। कठिन परिस्थितियों का समाधान निकालने में सफलता मिल सकती है। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास मजबूत होगा।

मिथुन -मिथुन राशि के जातकों को आज अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि किसी भी विवाद या अनावश्यक बहस से दूरी बनाए रखना उचित रहेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखने से आगे चलकर लाभ मिल सकता है।

कर्क -कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से जुड़ा हो सकता है। मेहनत और समर्पण के बल पर महत्वपूर्ण सफलता मिलने की संभावना है। प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। परिवार और करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा तथा नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं।

सिंह-सिंह राशि के जातकों के लिए आज प्रभावशाली लोगों से मुलाकात के अवसर बन सकते हैं। भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह समय अनुकूल माना जा सकता है। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत महसूस होगी।

कन्या -कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से रुके कार्यों में प्रगति हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार से आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में विशेषकर भाई-बहनों के साथ संबंध पहले से बेहतर हो सकते हैं। कार्यों में निरंतरता बनाए रखना लाभदायक रहेगा।

तुला -तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है। व्यापार में सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन कुछ प्रशासनिक कार्यों में विलंब हो सकता है। पुराने परिचितों से मुलाकात हो सकती है। निजी संबंधों में अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना उचित रहेगा।

वृश्चिक-वृश्चिक राशि के जातक आज अपने संसाधनों और सुविधाओं में वृद्धि के लिए प्रयासरत रहेंगे। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की संभावना है। महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में जा सकते हैं। दैनिक जीवन में सुविधाओं का विस्तार होने के संकेत भी मिल रहे हैं।

धनु -धनु राशि के जातकों के लिए आज कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं। निर्माण और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि किसी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले पूरी योजना बनाना आवश्यक रहेगा। निजी संबंधों में अपेक्षित परिणाम न मिलने से मन थोड़ा विचलित हो सकता है।

मकर -मकर राशि के जातकों के लिए आज शिक्षा और अध्ययन से जुड़े कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का समय रहेगा। एकाग्रता के साथ किए गए प्रयास भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं। निजी जीवन में नए संबंधों के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। अनावश्यक यात्राओं से बचना बेहतर रहेगा।

कुंभ -कुंभ राशि के जातकों के लिए आज सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में सम्मान बढ़ने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में प्रभाव मजबूत हो सकता है। आलोचनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। निजी संबंधों में विश्वास और मजबूती बनी रहेगी।

मीन -मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन राहत देने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही मानसिक चिंताओं में कमी आएगी। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और संतान से जुड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है।

स्वर्णिम लक्ष्यों के साथ 2047 तक कृषि महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

प्रदेश सरकार तिलहन के उत्पादन को 63 लाख मीट्रिक टन व उत्पादकता 22 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तथा दलहन के उत्पादन को 57 लाख मीट्रिक टन व उत्पादकता 20 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे राज्य में कुल फसलों का उत्पादन 1160 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। धरती माता की उर्वरता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है, जिसके तहत मिट्टी में जीवांश कार्बन के स्तर को वर्तमान 0.8 से बढ़ाकर 1.0 तक करने का उत्कृष्ट लक्ष्य रखा गया है। इससे कृषि की उपज में भारी बढ़ोतरी होने के साथ-साथ दीर्घकालिक कृषि स्थिरता को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर हरी खाद, कंपोस्ट और उन्नत जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डबल इंजन सरकार के भगीरथ प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश की 30 लाख हेक्टेयर बंजर व ऊसर भूमि का पूरी तरह से वैज्ञानिक उपचार करके उसे अत्यंत उपजाऊ और कृषि योग्य बनाया जा रहा है। इस उपचारित भूमि पर दलहन, तिलहन व अन्य नकदी फसलों का प्रचुर उत्पादन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों में बहुत बड़ा सुधार होगा।

उत्तर प्रदेश, देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ-साथ भारत की कृषि व्यवस्था का भी मुख्य आधार स्तंभ माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ समर्पित होकर कार्य कर रही है। "विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन" के अंतर्गत राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक, तकनीक-संचालित, टिकाऊ और अत्यधिक लाभकारी बनाने का एक महा-संकल्प लिया है। डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी नीतियों, सुशासन और दूरदर्शी विजन का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक राज्य को एक वैश्विक कृषि महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश की संभावित छह ट्रिलियन डॉलर की कुल अर्थव्यवस्था में अकेले कृषि क्षेत्र से एक ट्रिलियन यू0एस0 डॉलर का योगदान सुनिश्चित करने का एक अभूतपूर्व और अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस विराट संकल्प को सिद्ध करने के लिए राज्य सरकार संपूर्ण प्रदेश में नवाचार को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है तथा जलवायु अनुकूल प्रजातियों को निरंतर विकसित कर रही है। इस ऐतिहासिक आर्थिक महा-लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डबल इंजन सरकार भूमि के कण-कण का प्रभावी उपयोग कर किसानों की समृद्धि सुनिश्चित कर रही है। वर्तमान समय में प्रदेश की फसल सघनता जो वर्ष 2023-24 में 182 प्रतिशत दर्ज की गई है, उसे विजन 2047 के तहत बढ़ाकर 250 प्रतिशत तक करने का शानदार और प्रभावी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा बेहतर सिंचाई प्रबंधन, वैज्ञानिक फसल नियोजन, गुणवत्ता युक्त कृषि निवेशों के सुचारू प्रबंधन और सर्वोत्कृष्ट नवीन तकनीकों को धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके साथ ही फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, सरकार ने वर्ष 2047 तक खाद्यान्नों के बेहद सटीक और विशाल लक्ष्य तय किए हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकार गेहूं का उत्पादन बढ़ाकर 550 लाख मीट्रिक टन और उसकी उत्पादकता 55 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी प्रकार धान का उत्पादन लक्ष्य 320 लाख मीट्रिक टन और उत्पादकता 45 कुन्तल प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है, जबकि मक्के का उत्पादन 110 लाख मीट्रिक टन और उत्पादकता को 70 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाने की शानदार रूपरेखा तैयार की जा चुकी है।

प्रदेश सरकार तिलहन के उत्पादन को 63 लाख मीट्रिक टन व उत्पादकता 22 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तथा दलहन के उत्पादन को 57 लाख मीट्रिक टन व उत्पादकता 20 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे राज्य में कुल फसलों का उत्पादन 1160 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। धरती माता की उर्वरता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है, जिसके तहत मिट्टी में जीवांश कार्बन के स्तर को वर्तमान 0.8 से बढ़ाकर 1.0 तक करने का उत्कृष्ट लक्ष्य रखा गया है। इससे कृषि की उपज में भारी बढ़ोतरी होने के साथ-साथ दीर्घकालिक कृषि स्थिरता को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर हरी खाद, कंपोस्ट और उन्नत जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डबल इंजन सरकार के भगीरथ प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश की 30 लाख हेक्टेयर बंजर व ऊसर भूमि का पूरी तरह से वैज्ञानिक उपचार करके उसे अत्यंत उपजाऊ और कृषि योग्य बनाया जा रहा है। इस उपचारित भूमि पर दलहन, तिलहन व अन्य नकदी फसलों का प्रचुर उत्पादन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों में बहुत बड़ा सुधार होगा।

उत्तर प्रदेश की कृषि को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए डबल इंजन सरकार इसे आधुनिक तकनीक से पूरी तरह लैस कर रही है। सरकार ने प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को आधुनिक कृषि मशीनरी से संतृप्त करने की योजना बनाई है, जिससे राज्य में लगभग 75 प्रतिशत मशीनीकृत आधारित कृषि को शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों की कार्यक्षमता और सुविधा को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अत्याधुनिक उपकरणों, ट्रेंच प्लांटर्स और अन्य सटीक उपकरणों का समावेश किया जा रहा है और महिलाओं की भागीदारी सुगम बनाने के लिए जेंडर फ्रेंडली यंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्री-टेक के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सरकार एआई, ड्रोन और रिमोट सेंसिंग तकनीकों पर आधारित एक एकीकृत एग्री-डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। इसके माध्यम से राज्य के किसानों को रियल-टाइम मौसम की सटीक जानकारी, प्रिसिजन फार्मिंग टूल्स और बेहतर निर्णय लेने वाली प्रणालियां आसानी से उपलब्ध कराई जा रही हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम आधारित सभी प्रकार की सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है, जिससे खेती को सुरक्षित बनाया जा सके। तकनीक के इसी क्रम में एआई आधारित पार्टिसिपेटरी पेस्ट मॉनिटरिंग के माध्यम से समय पर फसलों का सर्विलांस करके किसानों को खरपतवार, कीट, रोग और किसी भी संभावित प्रकोप से बचाव की अग्रिम जानकारी और प्रभावी नियंत्रण उपाय प्रदान किए जा रहे हैं। किसानों की आमदनी को दोगुने से भी अधिक करने के लिए गन्ने की मुख्य फसल के साथ सहफसली खेती को अत्यंत प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जा रहा है। आधुनिक तकनीक आधारित कृषि यंत्रों के प्रयोग से गन्ने के साथ-साथ सरसों, धनिया, मसूर, उड़द और मूंग जैसी फसलों की लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर के विशाल क्षेत्रफल पर अतिरिक्त खेती कराई जा रही है, जो किसानों की आय में सीधे तौर पर भारी वृद्धि कर रही है। राज्य की विभिन्न भू-जलवायु परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए सरकार आगामी पांच वर्षों के भीतर पांच भव्य बीज पार्क स्थापित करने जा रही है, जिसके बाद क्रमिक रूप से चार अन्य बीज पार्कों की भी स्थापना की जाएगी। बदलती वैश्विक और घरेलू मांगों के अनुरूप सरकार 20 प्रतिशत फसल विविधीकरण को लागू कर रही है, जिसमें मक्के के क्षेत्र को बढ़ाकर 50 लाख हेक्टेयर किया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने 'हर खेत में मेड़, हर मेड़ पर पेड़' के दूरदर्शी मंत्र के साथ कृषि वानिकी कार्यक्रम को एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप दे दिया है। इसके अंतर्गत तेजी से बढ़ने वाले और आर्थिक रूप से अत्यधिक मूल्यवान पौधों जैसे पॉपुलर, मिलिया डुबिया, ऑस्ट्रेलियन टीक, महोगनी और पाउलोनिया स्पीशीज का रोपण खेतों की मेड़ों पर कराया जा रहा है ताकि किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिल सके। सरकार का परम लक्ष्य नवीनतम तकनीकों, उच्च मूल्य वाली चिया, रामदाना, क्विनोआ और मखाना जैसी फसलों की खेती को पांच लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करके किसानों की आय को तीन गुना करना है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों का व्यापक क्षमता विकास किया जा रहा है। रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग में 25 प्रतिशत की भारी कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज को बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का शानदार लक्ष्य है। प्रदेश के समस्त निजी नलकूपों को शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा से संचालित करने की दिशा में भी सरकार पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक स्तर के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आई.आर.आर.आई. और सी.आई.पी. जैसे विश्वविख्यात संस्थानों की तर्ज पर इकरीसेट एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध संस्थान और कृषि इनोवेशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, वैश्विक मानकों के अनुरूप फसलों को उगाने और सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए विशेष निर्यात और प्रसंस्करण-उन्मुख क्लस्टर तेजी से विकसित किए जा रहे हैं। किसानों को किसी भी अप्रत्याशित संकट से बचाने के लिए फसल बीमा का दायरा बढ़ाते हुए अधिकतम कृषकों को बीमा कवरेज से आच्छादित किया जा रहा है और उन्हें समय पर शत-प्रतिशत क्षतिपूर्ति सुनिश्चित कराई जा रही है। साथ ही, नवीनतम कृषि तकनीकों को हर खेत तक पहुंचाने के लिए एक्सपोजर विजिट और आधुनिक माध्यमों से किसानों का सघन एवं व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता विकास निरंतर जारी है। निश्चित रूप से, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार द्वारा उठाए गए ये ऐतिहासिक, सुनियोजित और क्रांतिकारी कदम इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि राज्य सरकार अपने अन्नदाताओं के कल्याण और कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है।

-डॉ0 मनोज चन्द्रा

मेरठ में ग्रीन मोबिलिटी का नया सवेरा : ई-बसों से चमकेगी महानगर की यातायात व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष प्रयासों से मेरठ महानगर के निवासियों को जल्द ही आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार ने ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल के तहत मेरठ समेत 18 प्रमुख शहरों में 1725 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को हरी झंडी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने से मेरठ की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को न केवल एक नई गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय यात्रियों को भी दैनिक आवागमन में विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

वर्तमान समय में मेरठ में हो रहे तीव्र शहरीकरण और निजी वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण महानगर की यातायात प्रणाली पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम बेहद प्रभावी साबित होगा। नई ई-बसों के सड़कों पर उतरने से जहां शहरवासियों को सुरक्षित, आरामदायक और किफायती यात्रा का बेहतरीन विकल्प मिलेगा, वहीं वायु प्रदूषण और जाम की समस्या से भी बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में नगरीय परिवहन के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार की यह नीति अत्यंत दूरदर्शी है। वर्तमान में नगर विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा प्रदेश के 15 नगर निगम क्षेत्रों में 743 इलेक्ट्रिक बसों का सफल संचालन किया जा रहा है, जिनमें से 700 बसें पहले से ही जीसीसी मॉडल पर चल रही हैं। इस सफल प्रयोग के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए अब सरकार ने मेरठ पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 9 मीटर और 12 मीटर श्रेणी की नई एसी ई-बसों को शामिल करने का निर्णय लिया है। परियोजना को धरातल पर पूरी दक्षता के साथ उतारने के लिए लोक-निजी सहभागिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया गया है। योजना के अंतर्गत चयनित निजी ऑपरेटर ही बसों की खरीद, चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, योग्य चालकों एवं तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था तथा उनके पूर्ण संचालन व अनुरक्षण की जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित कड़े प्रदर्शन मानकों के आधार पर ही ऑपरेटरों को शुल्क का भुगतान किया जाएगा। यह संपूर्ण अनुबंध वाणिज्यिक संचालन की तिथि से 12 वर्षों की लंबी अवधि के लिए प्रभावी होगा। इस बड़ी परियोजना को आर्थिक रूप से व्यावहारिक और निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए सरकार द्वारा भारी वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार ने प्रत्येक 12 मीटर लंबी ई-बस पर 40 लाख रुपये तथा 9 मीटर लंबी ई-बस पर 35 लाख रुपये का आकर्षक अनुदान देने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त, डिपो निर्माण के लिए आवश्यक भूमि संबंधित नगर निगमों द्वारा बिना किसी वित्तीय बोझ के पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बस किराया और अन्य प्रयोक्ता शुल्क का निर्धारण सीधे राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार का यह निजी निवेश आधारित मॉडल सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार लाएगा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के चलते निजी ऑपरेटर यात्रियों को समयबद्ध संचालन, बेहतर व्यवहार और अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मेरठ में ई-बसों के इस बड़े विस्तार को सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में एक युगांतकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों का सफर सुगम होगा। यह संपूर्ण प्रयास उत्तर प्रदेश को देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण और उनके उपयोग का एक प्रमुख हब बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। वैश्विक परिदृश्य में जीवाश्म ईंधनों की सीमित उपलब्धता और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच, मेरठ जैसे तेजी से बढ़ते महानगर में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भी मील का पत्थर सिद्ध हो रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति के अंतर्गत दिए जा रहे अभूतपूर्व लाभों से राज्य में एक मजबूत ईवी इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में ये ई-बसें शून्य टेलपाइप उत्सर्जन सुनिश्चित करती हैं, जिससे महानगर में कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम होगा और वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा। आर्थिक दृष्टि से भी इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग आम जनता और फ्लीट ऑपरेटरों के लिए बेहद लागत प्रभावी साबित हो रहा है।

वर्तमान समय में मेरठ में हो रहे तीव्र शहरीकरण और निजी वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण महानगर की यातायात प्रणाली पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम बेहद प्रभावी साबित होगा। नई ई-बसों के सड़कों पर उतरने से जहां शहरवासियों को सुरक्षित, आरामदायक और किफायती यात्रा का बेहतरीन विकल्प मिलेगा, वहीं वायु प्रदूषण और जाम की समस्या से भी बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में नगरीय परिवहन के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार की यह नीति अत्यंत दूरदर्शी है। वर्तमान में नगर विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा प्रदेश के 15 नगर निगम क्षेत्रों में 743 इलेक्ट्रिक बसों का सफल संचालन किया जा रहा है, जिनमें से 700 बसें पहले से ही जीसीसी मॉडल पर चल रही हैं। इस सफल प्रयोग के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए अब सरकार ने मेरठ पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 9 मीटर और 12 मीटर श्रेणी की नई एसी ई-बसों को शामिल करने का निर्णय लिया है। परियोजना को धरातल पर पूरी दक्षता के साथ उतारने के लिए लोक-निजी सहभागिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया गया है।

पारंपरिक ईंधन की आसमान छूती कीमतों की तुलना में प्रति किलोमीटर परिचालन लागत बेहद कम होने के कारण यह उपभोक्ताओं, विशेषकर मध्यम वर्ग के मासिक बजट को बड़ी राहत प्रदान कर रहा है, जिससे देश की वित्तीय स्थिरता को भी बल मिल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को तीन पहिया और चार पहिया निजी वाहनों पर भी भारी क्रय सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित (डीबीटी) होती है। इसके अलावा, प्रदेश में पंजीकृत होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर शत-प्रतिशत रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क की पूर्ण छूट जैसी क्रांतिकारी पहल की गई है, जिससे ग्राहकों पर पड़ने वाला प्रारंभिक आर्थिक बोझ काफी कम हो गया है। इस प्रकार सरकार हर स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। मेरठ और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सरकार चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक विस्तार कर रही है। प्रमुख शहरी क्षेत्रों में हर तीन किलोमीटर पर और प्रमुख राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को तेजी से अमलीजामा पहनाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं के मन से श्रेंज एंग्जायटीश् यानी चार्ज खत्म होने का डर पूरी तरह समाप्त हो सके। इसके साथ ही, राज्य में अल्ट्रा-मेगा बैटरी प्लांट और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना के लिए वैश्विक स्तर पर निवेश आकर्षित किया जा रहा है, जिससे मेरठ सहित पूरे प्रदेश में स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। नगरीय परिवहन बेड़े में इन अत्याधुनिक बसों के शामिल होने से मेरठ की जनता को एक ध्वनि-रहित, प्रदूषण-मुक्त और वातानुकूलित यात्रा का उत्कृष्ट अनुभव मिलेगा तथा यह महानगर आने वाले समय में देश के सबसे स्वच्छ और विकसित शहरों की अग्रिम पंक्ति में शामिल होगा।

जनपद-मेरठ

जादुई डंडा: डॉ. ज्ञानवती दीक्षित की कल्पनाशीलता का जादुई संसार

हिंदी साहित्य की विशाल वाटिका में जहाँ विद्वत्ता की गंभीर छायाएँ फैली हैं, वहाँ कभी-कभी एक ऐसा फूल खिलता है जो बच्चों की हँसी, किशोरों की जिज्ञासा और वयस्कों की यादों को एक साथ छू जाता है। डॉ. ज्ञानवती दीक्षित की पुस्तक जादुई डंडा ठीक ऐसा ही एक रचनात्मक मोती है। अवधी साहित्य की गहन शोधार्थी, आधुनिक प्रबंध काव्यों की समीक्षक और बहुमुखी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध डॉ. दीक्षित ने इस पुस्तक के माध्यम से अपनी विद्वत्ता को बाल-मनोरंजन की नरम धूप में रूपांतरित कर दिया है।

लेखिका का साहित्यिक परिचय

डॉ. ज्ञानवती दीक्षित हिंदी और अवधी साहित्य की एक समर्पित विदुषी हैं। उनकी प्रमुख कृति अवधी की आधुनिक प्रबंध धाराः हिंदी का अद्भुत संदोह (2019) तीस वर्षों के अथक शोध का परिणाम है, जिसमें उन्होंने अवधी के 82 प्रबंध काव्यों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। गुरु डॉ. श्याम सुंदर मिश्र 'मधुप' को समर्पित यह ग्रंथ हिंदी साहित्य में अवधी की उपेक्षित धारा को मुख्यधारा से जोड़ने का उल्लेखनीय प्रयास है। इसी विद्वत्ता के बीच उन्होंने बाल-साहित्य की ओर भी कदम बढ़ाया। जादुई डंडा(जिसका लोकार्पण वृन्दा डिटेक्टिव के साथ हुआ) उनकी रचनात्मक बहुरंगी प्रतिभा का प्रमाण है। यह पुस्तक न केवल बच्चों के लिए मनोरंजक कहानी है, बल्कि नैतिक मूल्यों, कल्पनाशक्ति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली एक सशक्त रचना है।

जादुई डंडा का जादूः कथानक और थीम्स- जादुई डंडा शीर्षक ही अपनी ओर आकर्षित करता है। 'जादुई डंडा' – वह प्रतीक जो हर बच्चे के सपनों में छिपा होता है। पुस्तक में एक साधारण-सा बच्चा (या युवा पात्र) एक जादुई डंडे को प्राप्त करता है, जो केवल इच्छाओं को पूरा नहीं करता, बल्कि जिम्मेदारी, विवेक और सही-गलत के बीच का फर्क भी सिखाता है।

कल्पना कीजिएः एक छोटे से गाँव या आधुनिक शहर में रहने वाला पात्र, जो रोजमर्रा की समस्याओं – स्कूल की पढ़ाई, दोस्ती, परिवार, पर्यावरण या सामाजिक मुद्दों – से जूझ रहा है। अचानक उसके हाथ लगता है वह डंडा, जो चमक उठता है। लेकिन हर जादू के साथ एक शर्त जुड़ी होती है – गलत इच्छा से डंडा बेकार हो जाता है या उल्टा असर करता है। इस तरह लेखिका ने फैंटेसी को नैतिक शिक्षा का माध्यम बनाया है।

पुस्तक की खासियतें:

- सरल और प्रवाहपूर्ण भाषाः बच्चों की समझ के अनुकूल, परंतु शब्द-समृद्ध।
- कल्पनाशील चरित्रः जादुई प्राणी, बात करने वाले जानवर, या रहस्यमयी दुनिया।
- समसामयिक संदेशः पर्यावरण संरक्षण, दोस्ती की कीमत, आत्मविश्वास, ईमानदारी आदि।
- वृन्दा डिटेक्टिव के साथ पूरकताः एक में जासूसी रोमांच, दूसरे में जादुई रोमांच – दोनों बाल-मन को आकर्षित करने वाले।

यह रचना *हरि पॉटर* या *चंद्रकांता* जैसी परंपरा को भारतीय संदर्भ में आगे बढ़ाती प्रतीत होती है, जहाँ जादू वास्तविक जीवन की सीखों से जुड़ा होता है।

क्यों पढ़ें जादुई डंडा?
- बच्चों के लिएः रोमांच, जादू और सीख।
- किशोरों के लिएः प्रेरणा और आत्म-चिंतन।
- अभिभावकों-शिक्षकों के लिएः सकारात्मक पठन सामग्री।
- साहित्य प्रेमियों के लिएः बहुमुखी लेखिका की एक और सशक्त कृति।

साहित्यिक महत्व और अपील

डॉ. दीक्षित की विद्वत्ता यहाँ भी झलकती है। उन्होंने बाल-साहित्य को हल्का-फुल्का नहीं, बल्कि जिम्मेदार माध्यम माना है। जादुई डंडा बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के साथ-साथ उनकी रचनात्मकता को उड़ान देता है। अभिभावक इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें मनोरंजन के साथ मूल्य-शिक्षा का संतुलन है। आधुनिक युग में जहाँ स्क्रीन-टाइम बढ़ रहा है, ऐसी पुस्तकें बच्चों को कागजी दुनिया के जादू से जोड़ती हैं। लेखिका ने साबित किया कि गंभीर शोधकर्ता भी बच्चों के सपनों का वास्तुकार बन सकता है।

,जादुई डंडा सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक अनुभव है। डॉ. ज्ञानवती दीक्षित ने साबित किया कि साहित्य की कोई उम्र नहीं होती। यह पुस्तक उन हाथों में चमकेगी जो जादू पर विश्वास करते हैं और उन दिलों में बस जाएगी जो जादू पैदा करना जानते हैं। जादुई डंडा – एक पुस्तक जो कहती है: 'जादू तुम्हारे भीतर है, बस उसे सही दिशा दो।'

स्वामी-स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ला द्वारा अनवर ऑफसेट एम- 58, 59 बेसमेंट विकासदीप बिल्डिंग स्टेशन रोड लखनऊ से मुदित ई-4 सेक्टर-एम/29 अपोजिट उस्मान एन्क्लेव, अलीगंज-लखनऊ 226024 से प्रकाशित, सम्पादक रवि कुमार अवस्थी , मो0-9511151254
Mail: news@swatantraprabhat.com, R.NI NO. UPHIN/2012/43078 इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी आर वी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी भी कानूनी विवाद का निपटारा न्यायलय जनपद लखनऊ में ही होगा।

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में विदाई एवं सम्मान समारोह संपन्न

अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाने में कोई विलम्ब न करें :- संतोष कुमार मिश्रा वरिष्ठ प्रवक्ता

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

खैराबाद सीतापुर स्थानीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ तथा पूर्व माध्यमिक जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ खैराबाद के द्वारा संयुक्त रूप से पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्र की पदोन्नति एवं रायबरेली के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर स्थानांतरण के अवसर पर विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।इस अवसर पर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अपूर्व दीक्षित, प्रवक्ता मनीष पांडेय, ज़िला उपाध्यक्ष प्राथमिक वंदना दीक्षित, डॉक्टर अनुपम मिश्र, ब्लॉक अध्यक्ष जूनियर नरेश मिश्रा, प्राथमिक अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, संरक्षक बृजेन्द्र कुमार टी पी सिंह,वरिष्ठ उपाध्यक्ष काजिम हुसैन सिद्दीकी,

राज्य पुरस्कार प्राप्त नीलम कुमारी, ए आर पी संजीव पटेरिया, वीरेन्द्र कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक योगेन्द्र पांडेय ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर मालार्पण एवं द्वीप प्रज्जवलित करके पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्र एवं अन्य ने किया तत्पश्चात मुख्य अतिथि का माल्यार्पण तथा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तथा सरस्वती वंदना रुबीना बानो, नीलम कुमारी, शशि बाला ने कराई,ज्ञात हो कि संतोष कुमार मिश्र ने खैराबाद ब्लॉक में 2 अगस्त 2024 को कार्यभार ग्रहण किया था इससे पहले श्री मिश्र महोली, कसमंडा, आदि ब्लॉक में भी रह चुके थे जबकि पहली नियुक्ति 1998 में हुई थी।,श्री मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने कभी किसी को बिला वजह परेशान नहीं किया और किसी को कार्यालय बुलाने का भी कार्य न करके सीधे उसके कार्य को पूरा किया ताकि उसे दौड़ना न पड़े , यहां के शिक्षकों में प्रेम और संस्कार बहुत अच्छे हैं दूसरों की इज़्ज़त और उनका सम्मान करने में कोई कमी नहीं रखते विशेष रूप से आज की यह शिक्षकों की भीड़ और प्रेम व उत्साह को देख कर बहुत प्रसन्नता हुई है और सभी को आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग सदैव स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। इस अवसर पर दोनों संगठनों की ओर से ढेरों उपहार दिए गए तथा व्यक्तिगत रूप से भी शिक्षिकाओं तथा शिक्षकों ने दिया जबकि संकुल धरैंचा की ओर से श्री मिश्र को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए पण्डित दीन दयाल उपाध्याय अवार्ड से सम्मानित किया गया। नोडल संकुल शिक्षक काज़िम हुसैन तथा संकुल शिक्षक हसन जमाल रिज़वी फ़ैजुल हसन, रुचि तिवारी सरिता रानी वर्मा सुरेंद्र कुमार जितेन्द्र कुमार मनी तिवारी ने स्मृति चिन्ह तथा उपहार देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में पंकज कुमार रावत रमेश रस्तोगी आलोक कुमार प्रमोद यादव पवन कुमार सिंह मंत्री अमित त्रिपाठी सौरभ जायसवाल जमशेद आलम प्रदेश अध्यक्ष अपूर्व दीक्षित ने कहा कि शिक्षकों के पार्टी इतना लगाव और सहयोग करने वाला अधिकारी नहीं देखा वाक़ई श्री मिश्र सम्मान पाने के हकदार हैं जबकि टी पी सिंह और मनीष पांडेय ने आपके साहस और आपकी हिम्मत की सराहना करके हमेशा याद रखने की बात कही, अन्य संबोधन करने वालों में काज़िम हुसैन,इशरत अली, रुबीना बानो, नीलम कुमारी, वंदना दीक्षित,अनुपम मिश्र, संजीव पटेरिया, वीरेन्द्र, प्रतिमा मिश्रा आदि हैं जबकि स्वागत भाषण नरेश मिश्रा ने तथा आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन पवन कुमार सिंह ने व्यक्त किया।

साहित्य सृजन संस्थान, बिसवां द्वारा जरूरतमंद, मेधावी बच्चों को नि:शुल्क वितरित की गई पाठ्य पुस्तकें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर) शैक्षिक, सामाजिक, साहित्यिक सरोकारों को समर्पित अ. भा. संस्था 'साहित्य सृजन संस्थान' द्वारा क्षेत्र बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए बिसवां में निकट पशु चिकित्सालय, तहसील रोड पर स्थापित 'सृजन पुस्तकालय' में (हाई स्कूल इंटर के छात्र, छात्राओं को) नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी एवं स्कूल बैग उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका, चेयरमैन, पुष्पू जायसवाल उपस्थित रहे। संस्थान द्वारा उन्हें अंगवस्त्र, स्मृतिचिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। समाजसेवी गिरिधर अग्रवाल, सौरभ बंसल के द्वारा कृष्णा देवी गर्ल्स कॉलेज की कुछ छात्राओं को उनकी पाठ्यक्रम की पुस्तकें, स्टेशनरी और स्कूल बैग प्रदान किया गया। इसी क्रम में कुछ अन्य बच्चों को उनकी स्कूल किट उनके विद्यालय भेजी गई। इस अवसर चेयरमैन ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तकालय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं और एक प्रबुद्ध पाठक वर्ग का निर्माण करते हैं। सृजन पुस्तकालय का यह प्रयास सराहनीय है। हमारी शुभकामनाएं और भरपूर सहयोग संस्थान को सदैव सुलभ रहेगा। संस्थान के संस्थापक /अध्यक्ष साहित्यकार संदीप मिश्र सरस ने बताया कि संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष क्षेत्र के मेधावी जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क स्कूल बुक किट उपलब्ध कराई जाती है। ये बच्चे अपनी मेधा के बल पर सफलता अर्जित करके बिसवां का नाम पूरी दुनिया में जब रोशन करेंगे तो हमारे संस्थान का संकल्प सार्थक हो जाएगा। कार्यक्रम में कृष्णा देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य लक्ष्मी देवी, उप प्रधानाचार्य उषा मिश्रा, गंगा स्वरूप मिश्र, एडवोकेट मनोज गुप्ता, श्रीकांत मिश्रा, नीरज मिश्रा सभासद, हरिशंकर त्रिवेदी मुकुंद पांडेय, अमन बाजपेई आदि एवं बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं की साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक पुस्तकों के साथ-साथ पर्याप्त कंपटीशन बुक्स की व्यवस्था है। प्रतिवर्ष विभिन्न महाविद्यालयों के अन्यान्य शोध छात्र छात्राएं पुस्तकालय द्वारा उपलब्ध पुस्तकों से अपने लघु शोध प्रबंध तैयार करते हैं। सृजन पुस्तकालय द्वारा समय-समय पर बच्चों को विभिन्न स्कूल, कोचिंग सेंटर में एडमिशन एवं छूट का सहयोग दिलाया जाता है और छात्र-छात्राओं के लिए मोटिवेशनल क्लासेस एवं करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। अब पुस्तकालय में कंप्यूटर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था संचालित हो गई है।

नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा को महापौर सुषमा खर्कवाल ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने शनिवार को उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने मंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर जनसेवा के लिए मंगलकामनाएं व्यक्त कीं। इस अवसर पर नगर निगम लखनऊ के कार्यकारिणी उपाध्यक्ष एवं पार्षद दल के उपनेता सुशील तिवारी 'पम्मी' सहित कई पार्षद भी मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने मंत्री ए.के. शर्मा को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ, सुखी और यशस्वी जीवन की कामना की। महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि ए.के. शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में नगर विकास, शहरी आधारभूत सुविधाओं और जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। महापौर ने प्रभु श्रीराम से प्रार्थना करते हुए कहा कि मंत्री को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और जनसेवा का निरंतर सामर्थ्य प्राप्त हो तथा उनके नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे।

बीजेएसपी जिला अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जताया आक्रोश

अभियुक्त महेन्द्र सोनी के खिलाफ डीजीपी , पुलिस आयुक्त मुंबई, नोडल अधिकारी साइबर क्राइम और SP बांदा को भेजा पत्र

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने फोन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना दी कि जब वे गांव स्योंढा जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि 'मरवा जाओगे, ऐ होगा वो होगा। इस गंभीर मामले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह ने कहा कि पार्टी पहले ही इस संबंध में अभियुक्त महेन्द्र सोनी निवासी मुंबई कथित RSS कैडर के विरुद्ध शिकायत पत्र तैयार कर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त मुंबई, नोडल अधिकारी साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश लखनऊ और पुलिस अधीक्षक बांद को स्पीडपोस्ट के माध्यम से भेज चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह का बयान: BJSP के कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने वाले चाहे कितने भी बड़े हों, हम डरने वाले नहीं हैं। हमने शिकायत पत्र सभी बड़े अधिकारियों को भेज दिया है।

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भारतीय जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह ने आज बताया कि जिला बांदा के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव को कुछ अराजक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज दिनांक 11.07.2026 को सुबह 9:35 बजे जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने फोन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना दी कि जब वे गांव स्योंढा जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि 'मरवा जाओगे, ऐ होगा वो होगा ।

इस गंभीर मामले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह ने कहा कि पार्टी पहले ही इस संबंध में अभियुक्त महेन्द्र सोनी निवासी मुंबई कथित RSS कैडर के विरुद्ध शिकायत पत्र तैयार कर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त मुंबई, नोडल अधिकारी साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश लखनऊ और पुलिस अधीक्षक बांद को स्पीडपोस्ट के माध्यम से भेज चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह का बयान: BJSP के कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने वाले चाहे कितने भी बड़े हों, हम डरने वाले नहीं हैं। हमने शिकायत पत्र सभी बड़े अधिकारियों को भेज दिया है। महेन्द्र सोनी और उसके आदमी जिला अध्यक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं और कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर जिला अध्यक्ष को एक खरोंच भी आई तो BJSP पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। पुलिस प्रशासन से मांग है कि 24 घंटे में दोषियों को गिरफ्तार कर सुरक्षा मुहैया कराई जाए।' राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।भारतीय जन समाज पार्टी की मांग: 1. तत्काल FIR दर्ज कर अभियुक्त महेन्द्र सोनी और उसके साथियों की गिरफ्तारी हो। 2. जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए। 3. साइबर सेल द्वारा धमकी देने वालों की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए।

बक्शी का तालाब इंटर एवं कृषि महाविद्यालय मे वृक्षारोपण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर- वृक्षारोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम पर इंटर कॉलेज एवं चंद्रभान गुप्त कृषि महाविद्यालय में वृक्षारोपण महा अभियान की शुरुआत की गई। बक्शी का तालाब इंटर कॉलेज के प्रांगण में डॉ बी पी राम निदेशक उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश शासन, डॉ डीपी सिंह जिला उद्यान अधिकारी, दिलीप कुमार वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक, रमेश यादव प्रभारी उद्यान बीकेटी आदि के साथ विद्यालय प्रधानाचार्य अशोक कुमार बाजपेई पूर्व प्रधानाचार्य डॉ ? के के शुक्ला,डॉ ? राजेश मिश्रा, पन्नालाल गुप्ता, अनिल कुमार गौतम, हरिश्चंद्र सिंह रामजी यादव, अजय कुमार, चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के डॉ जसकरन, डॉ हृदय नारायण तिवारी, रणजीत सिंह, प्रेम बाबू चौरसिया तथा विद्यालय के सभी कर्मचारी व छात्र- छात्राओं ने बड़े उत्साह से वृक्षारोपण किया और उनकी सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड लगाए। चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बक्शी का तालाब इंटर कॉलेज में देसी आम , नीम महुआ, कैथा, बेल चिलवल तथा बालम खीरा, सहजन, अमरूद सहित 51 पौधे रोपित किए गए तथा चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के हाजीपुर कृषि फार्म पर 100 से अधिक पौधे लगाए गए।

संक्षिप्त खबरें

विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, बूथ सशक्तीकरण पर रहेगा पूरा फोकस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद शनिवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक में आगामी चुनावी तैयारियों, बूथ सशक्तीकरण और जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने नई कार्यकारिणी तथा विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय बनाने पर जोर दिया। पार्टी ने प्रत्येक बूथ को भाजपा की जीत का मजबूत आधार बनाने और विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाने का निर्णय लिया।

सूचना

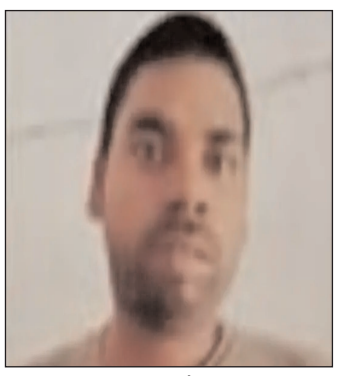

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम राजेन्द्र कुमार गुप्ता आयु लगभग 49 वर्ष पुत्र स्व0 सिया राम गुप्ता, निवासी 543/85 पीएन-78बी, संगम नगर, कश्मीरी बाग, मल्हपुर, राजाजीपुरम्, लखनऊ, उ0प्र0- 226017 मै उपरोक्त पते का स्थायी निवासी एवं भारतीय नागरिक है। मेरी पुत्री शुभी गुप्ता (Shubhi Gupta) ने हाईस्कूल की परीक्षा COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS, NEW DELHI से सन् 2026 में उत्तीर्ण की थी। जिसका यूनिक आई0डी0 (रजि0 नंबर)-8779035 व अनुक्रमांक- 1268196 है। यह कि शपथी की पुत्री के हाईस्कूल के अंक प्रमाण-पत्र में उसकी माता का नाम त्रुटिवश KUSHBOO GUPTA अंकित हो गया है जबकि शपथी की पुत्री की माता का सत्य, सही व वास्तविक नाम KHUSHBOO GUPTA है, जो कि शपथी की पुत्री की माता के आधार कार्ड में अंकित है। अपनी पुत्री के उक्त वर्णित हाईस्कूल के अंक प्रमाण-पत्र में अपनी पुत्री की माता का नाम KUSHBOO GUPTA के स्थान पर KHUSHBOO GUPTA अंकित करवाना चाहता है. जो कि शपथी की पुत्री की माता का सत्य, सही व वास्तविक नाम है।

मलिहाबाद में 30 वर्षीय युवक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता, पुलिस ने जारी की गुमशुदगी की सूचना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। मलिहाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला बस्ती धनवन्तराय कस्बा निवासी 30 वर्षीय पंकज पुत्र श्रीराम बीती 5 जुलाई 2026 की रात से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं। युवक के अचानक गायब होने से परिजनों में चिंता का माहौल है। काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर आमजन से सहयोग की अपील की है। मलिहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह भाटी के अनुसार, पंकज 5 जुलाई की रात करीब 12 बजे से लापता हैं। उनका पता मोहल्ला बस्ती धनवन्तराय कस्बा, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ बताया गया है। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा

जारी गुमशुदगी सूचना के अनुसार, पंकज का रंग सांवला, चेहरा गोल, शरीर दुबला-पतला तथा कद लगभग 5.5 फीट है। पुलिस ने यह भी बताया है कि उनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं बताई गई है, जिसके चलते उनकी सुरक्षित बरामदगी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मलिहाबाद पुलिस लगातार युवक की तलाश में जुटी हुई है और संभावित स्थानों पर जांच

काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर आमजन से सहयोग की अपील की है। मलिहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह भाटी के अनुसार, पंकज 5 जुलाई की रात करीब 12 बजे से लापता हैं। उनका पता मोहल्ला बस्ती धनवन्तराय कस्बा, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ बताया गया है।

की जा रही है। आसपास के थानों को भी सूचना भेजी गई है ताकि युवक का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को पंकज के संबंध में कोई भी जानकारी मिले या वह कहीं दिखाई दें, तो तत्काल थाना मलिहाबाद पुलिस को सूचित करें। पुलिस का कहना है कि नागरिकों की एक छोटी-सी सूचना भी युवक को सकुशल खोजने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

मुख्यमंत्री योगी के संभावित आगमन से गोविंद साहब धाम में हलचल तेज, तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आलापुर, अंबेडकरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र स्थित महात्मा गोविंद साहब की पावन तपोस्थली अहिरौली गोविंद साहब के संभावित दौरे को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यदि गोविंद साहब धाम पहुंचते हैं तो माना जा रहा है कि वह संत परंपरा और सामाजिक समरसता का संदेश देने के साथ-साथ क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि महात्मा गोविंद साहब की तपोस्थली का व्यापक कायाकल्प कराया जाएगा तथा इसे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में विकसित करने की दिशा में बड़ा निर्णय

लिया जा सकता है। क्षेत्रवासियों को यह भी आशा है कि पूर्वांचल के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध गोविंद साहब मेले को राजकीय मेले का दर्जा प्रदान करने की घोषणा हो सकती है। वर्षों से चली आ रही इस मांग के पूरी होने से धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इसी के साथ रामनगर, कटेहरी और भीटी बाजार को नगर पंचायत बनाए जाने की चर्चाएं भी तेज हैं। विशेष रूप से रामनगर को नगर पंचायत बनाए जाने की सभी आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शासन स्तर पर अंतिम स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के दौरान इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

मछरेहटा में नवागत खण्ड शिक्षा अधिकारी का भव्य स्वागत कार्यक्रम जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ द्वारा सम्पन्न

शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तत्काल बताएं सिमी निगार खण्ड शिक्षा अधिकारी मछरेहटा

मछरेहटा सीतापुर नवागत खण्ड शिक्षा अधिकारी के प्रथम दिन पने कार्यालय में आगमन पर जूनियर हाईस्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ मछरेहटा ने खण्ड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार मैडम का उनके कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया,इस दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा मैडम को बुके भेंट कर अत्यंत आत्मीयता के साथ स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। स्वागत समारोह के उपरांत शिक्षक संघ और खण्ड शिक्षा अधिकारी के बीच ब्लॉक में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर एक सकारात्मक बैठक हुई। जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष पवन शुक्ल व प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मुकेश दीक्षित द्वारा आदरणीया खंड शिक्षा अधिकारी महोदया से बीआरसी व विद्यालय स्तर शिक्षकों की समस्याओं पर सार्थक चर्चा हुई, महोदया ने आशान्वित किया कि शिक्षकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण कराया जाएगा। इस स्वागत कार्यक्रम में पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ मछरेहटा के अध्यक्ष पवन शुक्ल,मंत्री सुनील यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मुकेश दीक्षित, प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष संदीप यादव जी,उपाध्यक्ष आरती श्रीवास्तव जी,कोषाध्यक्ष राशिद हुसैन,वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरज मिश्रा,लोकेंद्र कटारा, सियालाल,संतोष शुक्ल जी सहित ब्लॉक कार्यकारिणी के तमाम सम्मानित पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

विश्व युवा कौशल दिवस पर युवाओं को योगी सरकार का तोहफा, 74 जिलों में लगेंगे वृहद रोजगार मेले

13 और 14 जुलाई को आयोजित होंगे रोजगार मेले, 'जीरो पॉवर्टी' अभियान के युवाओं और दिव्यांगजनों को मिलेगी विशेष प्राथमिकता

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'हर हाथ को हुनर, हर हुनर को रोजगार' संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (क्षछरू) 13 और 14 जुलाई को प्रदेश के 74 जिलों में वृहद राज्य स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन करेगा। इन रोजगार मेलों के माध्यम से प्रशिक्षित एवं शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं

उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि योगी सरकार ने पिछले नौ वर्षों में कौशल विकास को नई पहचान दिलाई है। आज उत्तर प्रदेश के आईटीआई और स्किल सेंटर से प्रशिक्षित युवा देश-विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 74 जिलों में एक साथ आयोजित रोजगार मेले 'हर हुनर को सम्मान, हर युवा को रोजगार' के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार 'जीरो पॉवर्टी अभियान' के तहत चिन्हित अत्यंत गरीब परिवारों के युवाओं और दिव्यांगजनों को रोजगार मेलों में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े युवाओं तक रोजगार के अवसर पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि रोजगार मेलों का आयोजन जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) तथा कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयकों के समन्वय से किया जाएगा। जिलाधिकारियों को कार्यक्रम स्थल चयन, निजी उद्योगों एवं कंपनियों को आमंत्रित करने तथा प्रशिक्षित युवाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन रोजगार मेलों में प्रदेश का कोई भी इच्छुक युवा-युवती भाग ले सकता है। यूपीएसडीएम, डीडीयू-जीकेवाई (DDU-GKY) तथा 'प्रोजेक्ट प्रवीण' के तहत प्रशिक्षित युवाओं के अलावा औपचारिक शिक्षा पूरी कर चुके युवाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 'जीरो पॉवर्टी अभियान' से जुड़े युवाओं को चयन प्रक्रिया में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार मेलों में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए रैंप, सुगम आवागमन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी मेला स्थलों पर क्यूआर कोड की व्यवस्था होगी। सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती तथा पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। मिशन निदेशक ने बताया कि प्रत्येक रोजगार मेले के समापन के बाद संबंधित जिला प्रशासन चयनित एवं नियुक्त युवाओं की अंतिम रिपोर्ट मिशन मुख्यालय को भेजेगा, ताकि रोजगार उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी की जा सके।

नई रणनीति के साथ विधानसभा चुनावी मैदान में उतरी सपा, हर बूथ पर तैयार होंगे 50 डिजिटल योद्धा

लखनऊ। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) ने प्रदेशव्यापी घर-घर संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर जिला एवं शहर इकाइयों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके जरिए सपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के साथ-साथ डिजिटल नेटवर्क का भी विस्तार करेगी। पार्टी की रणनीति के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गांवों, कस्बों और शहरी मोहल्लों में कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। इस दौरान पार्टी की नीतियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और भावी चुनावी घोषणाओं से संबंधित पत्रक वितरित किए जाएंगे। साथ ही आमजन को यह बताया जाएगा कि सपा की सरकार बनने पर प्रदेश में किस प्रकार के विकास और जनहितकारी कार्य किए जाएंगे। सपा की योजना के अनुसार प्रत्येक बूथ पर 50 नए 'डिजिटल योद्धा' जोड़े जाएंगे।

मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान, असम राइफल्स हमले के बाद सर्च ऑपरेशन तेज

लीलोन वैफेई अपहरण मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, मुख्यमंत्री बोले– दोषियों को नहीं बख्शेंगे

इंफाल/उखरूल(एजेंसी)। मणिपुर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों के बीच सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर संयुक्त अभियान शुरू किया है। उखरूल जिले में असम राइफल्स के काफिले पर हुए घातक हमले के बाद तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। वहीं, लीलोन वैफेई अपहरण मामले में राज्य सरकार ने दो आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए शेष आरोपियों की तलाश तेज करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, छह जुलाई को उखरूल पुलिस थाना क्षेत्र के नुंगशोंग खोंग इलाके में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया था। इस हमले में वारंट अधिकारी बलवंत सिंह और हवलदार सी।एम। सिंह शहीद हो गए थे। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, संदिग्ध उग्रवादियों ने काफिले को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। हमले के बाद आवासीय इलाकों, संवेदनशील मार्गों और आसपास के जंगलों में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। अभियान का उद्देश्य हमलावरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना, संभावित हथियारों के ठिकानों का पता लगाना और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस बीच, नागा उग्रवादी संगठन एनएससीएन (आईएम) ने हमले में किसी भी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है। संगठन ने बयान जारी कर कहा कि वह केंद्र सरकार के साथ युद्धविराम समझौते और शांति प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध है तथा ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करता जो वार्ता प्रक्रिया को प्रभावित करे। उधर, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने लीलोन वैफेई अपहरण मामले में त्वरित कार्रवाई का भरोसा देते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों द्वारा चिन्हित पांच संदिग्धों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिकता है तथा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 मई को तीन पादरियों की हत्या के बाद संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने लीलोन वैफेई क्षेत्र से करीब 18 लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से 12 लोगों को बाद में रिहा कर दिया गया, जबकि छह लोगों का अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि मैखान गांव के दौरे के दौरान पीड़ित परिवारों ने पांच संदिग्धों की पहचान की थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

खामेनेई के अंतिम संस्कार में ट्रंप विरोधी नारे गूंजे, अमेरिका ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी

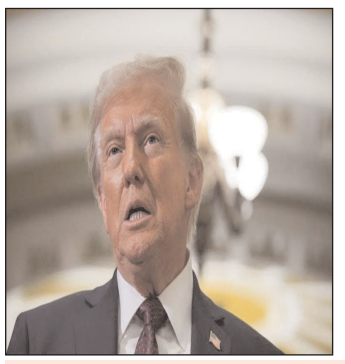

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी हत्या का खुले तौर पर आह्वान किए जाने के बाद शनिवार को ईरान को धमकी दी। इससे पश्चिम एशिया में जारी तनाव एक बार फिर उजागर हुआ है, जहां युद्ध समाप्त करने के लिए हुआ अंतरिम समझौता क्षेत्र में बार-बार हो रहे हमलों के कारण कमजोर पड़ता जा रहा है।ट्रंप की इस टिप्पणी से पहले अमेरिका ने ईरान से सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने की मांग की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला है और इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले पोतों पर अब हमले नहीं किए जाएंगे। तेहरान ने अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इसके बजाय उसने कहा है कि यह समुद्री मार्ग उसके नियंत्रण में रहना चाहिए और वहां से गुजरने वाले पोतों से उसे शुल्क वसूलने की अनुमति मिलनी चाहिए। ईरान का यह रुख होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग मानने की दशकों पुरानी व्यवस्था के विपरीत है। अमेरिका कुछ दिनों से ईरान को निशाना बनाकर फिर से हवाई हमले कर रहा है जिसके जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया के कई देशों पर हमले किए हैं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन पोतों पर ईरान के हमले के बाद शुरू हुए थे। ट्रंप ने अपनी वेबसाइट 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, ''एक हजार मिसाइलें तैयार हैं और उनका निशाना ईरान है। अगर ईरान सरकार अपनी धमकी पर अमल करती है तो इसके तुरंत बाद हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी।'' ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ''ईरान के सभी क्षेत्रों को पूरी तरह तबाह और नष्ट कर देगी।'

ट्रंप की इस टिप्पणी से पहले अमेरिका ने ईरान से सार्वजनिक रूप से यह घोषणा करने की मांग की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला है और इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले पोतों पर अब हमले नहीं किए जाएंगे। तेहरान ने अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इसके बजाय उसने कहा है कि यह समुद्री मार्ग उसके नियंत्रण में रहना चाहिए और वहां से गुजरने वाले पोतों से उसे शुल्क वसूलने की अनुमति मिलनी चाहिए। ईरान का यह रुख होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग मानने की दशकों पुरानी व्यवस्था के विपरीत है। अमेरिका कुछ दिनों से ईरान को निशाना बनाकर फिर से हवाई हमले कर रहा है जिसके जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया के कई देशों पर हमले किए हैं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन पोतों पर ईरान के हमले के बाद शुरू हुए थे।

रात को सोने से पहले जरूर करें ये काम, रहेंगी हेल्दी

अच्छी सेहत सिर्फ सही खानपान और नियमित व्यायाम से ही नहीं, बल्कि रात की अच्छी दिनचर्या से भी जुड़ी होती है। दिनभर की भागदौड़ के बाद शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए सोने से पहले अपनाई गई कुछ अच्छी आदतें आपकी नींद की गुणवत्ता और अगले दिन की ऊर्जा पर सकारात्मक असर डाल सकती हैं। वहीं, देर रात तक मोबाइल चलाना, अनियमित समय पर सोना या भारी भोजन करना जैसी आदतें स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सुबह तरोताजा महसूस करें और लंबे समय तक स्वस्थ रहें, तो सोने से पहले अपनी दिनचर्या में कुछ आसान बदलाव करना फायदेमंद हो सकता है। सोने का समय तय रखें और स्क्रीन से बनाएं दूरी अच्छी नींद के लिए रोजाना लगभग एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। इससे शरीर की प्राकृतिक बॉडी क्लॉक संतुलित रहती है। सोने से कम से कम 30 से 60 मिनट पहले मोबाइल, लैपटॉप या टीवी जैसी स्क्रीन से दूरी बनाना भी फायदेमंद माना जाता है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी (ब्लू लाइट) नींद आने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसकी जगह किताब पढ़ना, हल्का संगीत सुनना या शांत माहौल में समय बिताना बेहतर विकल्प हो सकता है। रात में बहुत ज्यादा तला-भुना या भारी भोजन करने से पाचन प्रभावित हो सकता है और नींद में भी परेशानी हो सकती है। कोशिश करें कि रात का खाना सोने से दो से तीन घंटे पहले खा लें और भोजन हल्का व संतुलित रखें। यदि देर रात भूख लगे, तो हल्का और पौष्टिक विकल्प चुनें। सही समय पर और संतुलित मात्रा में भोजन करने से शरीर को आराम मिलता है और पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। दिनभर का तनाव और मानसिक थकान कई बार नींद को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सोने से पहले कुछ मिनट गहरी सांस लेने, मेडिटेशन या हल्के रिलैक्सेशन अभ्यास करने से मन शांत हो सकता है। यह तनाव कम करने और शरीर को आराम की स्थिति में लाने में मदद कर सकता है। यदि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ मिनट से शुरुआत करें और अपनी सुविधा के अनुसार समय बढ़ाएं। अच्छी नींद के लिए बेडरूम का वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है। कमरे को साफ, शांत और आरामदायक रखें। बहुत तेज रोशनी या शोर से बचें और तापमान ऐसा रखें, जिसमें आपको आराम महसूस हो। सोने से पहले अगले दिन की जरूरी चीजें व्यवस्थित कर लेने से भी मन हल्का महसूस कर सकता है। यदि आपको लंबे समय से नींद आने में कठिनाई, बार-बार नींद टूटने या लगातार थकान जैसी समस्या हो रही है, तो किसी योग्य डॉक्टर से सलाह लेना उचित रहेगा। नियमित और स्वस्थ रात की दिनचर्या लंबे समय में आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों के लिए लाभदायक हो सकती है।

'द इंडिया स्टोरी' से कोर्टरूम ड्रामा में नजर आएंगी काजल अग्रवाल

फिल्म के प्रमोशन के दौरान काजल ने कहा कि कोर्टरूम ड्रामा हमेशा से उनकी पसंदीदा शैली रही है। वह लंबे समय से ऐसी चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली फिल्म की तलाश में थीं। उन्होंने कहा कि इस किरदार ने उन्हें एक कलाकार के रूप में खुद को और बेहतर तरीके से परखने का अवसर दिया। काजल के अनुसार, इस फिल्म में कई भावनात्मक दृश्य ऐसे थे जिन्हें निभाने के लिए उन्हें अभिनय करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वह उन पलों को वास्तविक रूप से जी रही थीं और आंसू, भावनाएं तथा संघर्ष पूरी तरह स्वाभाविक थे। उनका मानना है कि समय के साथ उनकी अभिनय क्षमता में परिपक्वता और गहराई आई है। उन्होंने कहा कि एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही होती है, जब वह अभिनय करना भूलकर पूरी तरह अपने किरदार में जीने लगे। उनके मुताबिक, इस फिल्म में उन्हें ऐसा अनुभव मिला, जिसने उनके अभिनय को नई ऊंचाई दी। फिल्म में काजल अग्रवाल के साथ अभिनेता श्रेयस तलपड़े भी मुख्य भूमिका में हैं। 'द इंडिया स्टोरी' में कीटनाशकों के दुरुपयोग, खाद्य पदार्थों में मिलावट और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। निर्माताओं के अनुसार, 'द इंडिया स्टोरी' 24 जुलाई को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बोलीं- लंबे समय से ऐसी फिल्म का था इंतजार, 24 जुलाई को होगी रिलीज

अभिनेत्री काजल अग्रवाल अपनी आगामी फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' के जरिए पहली बार दमदार कोर्टरूम ड्रामा में नजर आएंगी। फिल्म 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। काजल का कहना है कि वह लंबे समय से ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना चाहती थीं और इस फिल्म ने उनकी यह इच्छा पूरी कर दी। फिल्म में काजल अग्रवाल एडवोकेट अर्चना की भूमिका निभा रही हैं, जो एक आम नागरिक की ओर से उन शक्तिशाली कॉर्पोरेट कंपनियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ती हैं, जिन पर लोगों की जान जोखिम में डालने के आरोप हैं। कोर्टरूम ड्रामा और इन्वेस्टिगेटिव कहानी के माध्यम से फिल्म फूड सेफ्टी, कॉर्पोरेट जवाबदेही और पर्यावरण संरक्षण जैसे अहम मुद्दों को उठाती है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान काजल ने कहा कि कोर्टरूम ड्रामा हमेशा से उनकी पसंदीदा शैली रही है। वह लंबे समय से ऐसी चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली फिल्म की तलाश में थीं। उन्होंने कहा कि इस किरदार ने उन्हें एक कलाकार के रूप में खुद को और बेहतर तरीके से परखने का अवसर दिया। काजल के अनुसार, इस फिल्म में कई भावनात्मक दृश्य ऐसे थे जिन्हें निभाने के लिए उन्हें अभिनय करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वह उन पलों को वास्तविक रूप से जी रही थीं और आंसू, भावनाएं तथा संघर्ष पूरी तरह स्वाभाविक थे। उनका मानना है कि समय के साथ उनकी अभिनय क्षमता में परिपक्वता और गहराई आई है। उन्होंने कहा कि एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती वही होती है, जब वह अभिनय करना भूलकर पूरी तरह अपने किरदार में जीने लगे। उनके मुताबिक, इस फिल्म में उन्हें ऐसा अनुभव मिला, जिसने उनके अभिनय को नई ऊंचाई दी। फिल्म में काजल अग्रवाल के साथ अभिनेता श्रेयस तलपड़े भी मुख्य भूमिका में हैं। 'द इंडिया स्टोरी' में कीटनाशकों के दुरुपयोग, खाद्य पदार्थों में मिलावट और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है। निर्माताओं के अनुसार, 'द इंडिया स्टोरी' 24 जुलाई को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों पर अभद्र टिप्पणियां करने और दस्तावेज़ फेंकने वाले वादकारी को अदालत कक्ष से बाहर करवाया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक मामले की पैरवी खुद कर रहे याचिकाकर्ता ने पहले जजों को 'न्यायिक सेवक' कहकर संबोधित किया। ये वकील इतने में भी नहीं रूका और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को आदेश देने की कोशिश की और इसके बाद कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके बाद जब कोर्टरूम स्टॉफ ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो याचिकाकर्ता ने कोर्टरूम में कागज भी हवा में उछाल दिए। हालात बिगड़ते देख सुरक्षाकर्मियों ने उसे कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया। हालांकि, पूरे घटनाक्रम के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ अवमानना या दूसरी दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं करने का फैसला किया। याचिकाकर्ता की टिप्पणी पर पीठ में शामिल जस्टिस केवी विश्वनाथन ने हैरानी जताई। उन्होंने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह अदालत और न्यायाधीशों को आदेश दे रहा है? इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। आरोप है कि याचिकाकर्ता ने CJI सूर्यकांत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने हाथ में मौजूद कागजात भी हवा में उछाल दिए। अचानक हुए इस घटनाक्रम से कोर्टरूम में मौजूद वकील और अन्य लोग हैरान रह गए। याचिकाकर्ता के व्यवहार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षाकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुरक्षाकर्मी प्रबल प्रताप को कोर्टरूम से बाहर लेकर गए। बताया गया कि कुछ समय तक उसे अदालत परिसर में ष्ठस्कक्कार्यालय के अंदर रोका गया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठा कि क्या याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस में स्नढ्ढक्र दर्ज होगी या अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में हंगामा करने वाले याचिकाकर्ता की पहचान प्रबल प्रताप के रूप में बताई गई है।

वह पेशे से वकील बताया जा रहा है और अपने मामले में स्वयं याचिकाकर्ता के रूप में अदालत के सामने पेश हुआ था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रबल प्रताप ने पीठ के सामने अपनी मांग रखते हुए जजों को 'न्यायिक सेवक' कहकर संबोधित किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण रही। अदालत के कामकाज में व्यवधान और न्यायाधीशों के खिलाफ कथित अपशब्दों के इस्तेमाल के बावजूद पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना या दूसरी दंडात्मक कार्यवाही शुरू नहीं करने का फैसला किया। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने स्पष्ट किया कि अदालत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं करती। अदालत ने याचिकाकर्ता के मामले से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद उसकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) भी खारिज कर दी। मामले में अदालत की एक टिप्पणी ने सभी का ध्यान खींचा। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि याचिकाकर्ता बहुत परेशान था और उसका व्यवहार उसकी हताशा का नतीजा था। अदालत ने कहा कि उसे याचिकाकर्ता के प्रति केवल सहानुभूति है।

लापता है कुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा? केरल हाईकोर्ट ने रद्द की पुलिस सुरक्षा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। वायरल गर्ल मोनालिसा एक बार फिर चर्चाओं में हैं। वजह है कि केरल हाई कोर्ट ने आज शुक्रवार को मोनालिसा को सुरक्षा देने की बात कहने वाले अपने पिछले आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश में पुलिस को मोनालिसा को सुरक्षा देने की बात कही गई थी, जब उनके पति पर उनके अपहरण का आरोप लगा था। लड़की के वकील पी।एस। अनीशाद ने बताया कि पुलिस ने जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस को बताया कि जब उन्होंने सुरक्षा आदेश को लागू करने की कोशिश की, तो लड़की का पता नहीं चल सका। वकील अनीशाद ने कहा कि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब लड़की सुरक्षा की मांग करते हुए संपर्क करे, तो उसे सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। पुलिस सुरक्षा का हाई कोर्ट का आदेश लड़की की उस याचिका पर आया था, जिसमें उसने अपनी जान की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार और एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश देने की मांग की थी। लड़की के पति फरमान पर उसके अपहरण का आरोप है। यह मामला मध्य प्रदेश पुलिस ने उसके पिता की शिकायत पर दर्ज किया था, जिन्होंने दावा किया है कि वह नाबालिग है। मोनालिसा तब वायरल हो गई थीं, जब एक कंटेंट क्रिएटर ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए उनका एक वीडियो शेयर किया था।

लड़की के वकील पी।एस। अनीशाद ने बताया कि पुलिस ने जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस को बताया कि जब उन्होंने सुरक्षा आदेश को लागू करने की कोशिश की, तो लड़की का पता नहीं चल सका। वकील अनीशाद ने कहा कि कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब लड़की सुरक्षा की मांग करते हुए संपर्क करे, तो उसे सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है। अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।

मासूम आरव हत्याकांड में कातिल विराज को फांसी; सजा सुनते ही रो पड़ा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई को दिनदहाड़े डेढ़ साल के मासूम आरव की बेरहमी से सड़क पर आठ बार पटक कर हत्या के आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखूपुर, सिविल लाइंस, बदायूं को जिला जज डा। बब्बू सारंग की अदालत ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई। इससे पहले बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया था। सजा सुनते ही विराज रोने लगा। पुलिस अभिरक्षा में विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को पुलिस दोपहर ढाई बजे करीब जेल से कोर्ट लेकर पहुंची थी। यहां अभियोजन और बचाव पक्ष के सामने अदालत ने आरोपी को बच्चे की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने कहा, अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्य पूर्ण हैं। घटना बेहद जघन्य है। विराज को सजा का एलान होने के बाद पुलिस उसे वापस जेल ले गई। इस दौरान उसके चेहरे पर सजा का खौफ साफ था। इधर, मृतक आरव की नानी पिंकी देवी भी पहुंची थी। उन्होंने सजा पर खुशी जताई। शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई की दोपहर विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने रिश्ते की भाभी रति से शादी करने की जिद पूरी न होने पर उसके डेढ़ साल के मासूम बेटे आरव को सड़क पर बेरहमी से आठ बार पटक-पटककर मार डाला था। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार देर रात ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। मूल रूप से अरांव निवासी रति देवी की शादी फरवरी 2024 में बदायूं निवासी सुमित कुमार से हुई थी। पति से अनबन के कारण वह 5 महीने से मायके में रह रही थी। इसी का फायदा उठाकर सुमित के फुफेरे भाई विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखूपुर, बदायूं ने रति को मदद के भरोसे में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद रति के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे रति ने ठुकरा दिया था। 30 मई को रति अपनी मां पिंकी देवी के साथ कानूनी राय लेने शिकोहाबाद आई थी। आरोपी विराज भी वहां पहुंच गया था। मासूम आरव को टॉफी दिलाने के बहाने बाहर ले गया था। घर से 50 मीटर दूर सुनसान सड़क पर उसने मासूम को 27 सेकंड के भीतर लगातार 8 बार पक्की सड़क पर पटका। बच्चे की मौत के बाद वह शव को दरवाजे पर फेंककर भाग गया था।

सजा सुनते ही विराज रोने लगा। पुलिस अभिरक्षा में विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को पुलिस दोपहर ढाई बजे करीब जेल से कोर्ट लेकर पहुंची थी। यहां अभियोजन और बचाव पक्ष के सामने अदालत ने आरोपी को बच्चे की हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने कहा, अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्य पूर्ण हैं। घटना बेहद जघन्य है। विराज को सजा का एलान होने के बाद पुलिस उसे वापस जेल ले गई।

चेक बाउंस मामलों में हाईकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को सुनाई तीन महीने की सजा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस के सात मामलों में दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखते हुए प्रत्येक मामले में तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसले में राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में 1।05 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने का भी निर्देश दिया। इसमें से 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को और 25 हजार रुपये राज्य को दिए जाएंगे। अदालत ने राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी प्रत्येक मामले में 5 लाख 51 हजार 380 रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, श्री नवरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम कंपनी रजिस्ट्रार के अभिलेख से पहले ही हटाया जा चुका है। ऐसे में सत्र न्यायालय के आदेश के अनुसार कंपनी को केवल चेतावनी देकर छोड़ने के आदेश को भी हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट ने शिकायतकर्ता को पहले से किए गए भुगतान को ध्यान में रखते हुए ही जुर्माने की राशि तय की थी और उसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को पहले ही 2 ।25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अंतिम देय राशि की गणना करते समय इस रकम का समायोजन किया जाएगा। फैसले में अदालत ने कहा कि पहले की सुनवाई के दौरान एक पीठ इस मामले को गुण-दोष के आधार पर सुनने के पक्ष में नहीं थी। हालांकि, राजपाल यादव ने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की इच्छा जताई, इसलिए उन्हें राहत दी गई और कई अवसर दिए गए। हाईकोर्ट ने कहा कि बार-बार अवसर दिए जाने और अदालत के समक्ष दिए गए आश्वासनों के बावजूद राजपाल यादव ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। अंत में उन्होंने शिकायतकर्ता को कोई और भुगतान करने से इनकार कर दिया और यहां तक कहा कि वह जेल जाने के लिए तैयार हैं। अदालत ने टिप्पणी की, 'यदि कोई पक्षकार अदालत में दिए गए अनेक आश्वासनों का पालन करने के बजाय जेल जाना चुनता है तो यह उसका अपना निर्णय है। कानून कोई पटकथा नहीं है, जिसे किसी अभिनेता की इच्छा के अनुसार बदला जा सके।

अदालतें सभी के लिए समान रूप से कानून लागू करती हैं और वर्तमान पक्षकार भी इसका अपवाद नहीं हो सकता।' हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राजपाल यादव का आचरण ऐसा नहीं है कि उन्हें परिवीक्षा पर रिहाई का विवेकाधीन लाभ दिया जाए। हालांकि, अदालत ने राजपाल यादव को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए दो महीने का समय दिया। अदालत की कार्यवाही राजपाल यादव और उनकी पत्नी द्वारा दायर उन रिविजन याचिकाओं पर हुई, जिनमें उन्होंने सेशंस कोर्ट के 2019 के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल, सेशंस कोर्ट ने अप्रैल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा चेक-बाउंस के मामलों में उन्हें दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिनेता को छह महीने की सजा सुनाई थी। साल 2010 में राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए मुर्गाली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी से पांच करोड़ रुपये की राशि लोन के रूप में ली थी। 'अता पता लापता' बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। कथित तौर पर राजपाल यादव को आर्थिक नुकसान हुआ।

कर्ज के रूप में ली गई कंपनी की धनराशि वे लौटा नहीं पाए। कंपनी ने राजपाल यादव के खिलाफ केस किया और साथ ही यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने लोन वापस करने के लिए जो कुछ चेक जारी किए थे वे सभी बाउंस हो गए। एक्टर के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज किया गया। ये चेक फिल्म प्रोडक्शन के लिए दिए गए थे, लेकिन पैसे नहीं मिले।